



नेपाल के लोकप्रिय व्यंजन "नॉनवैज मोमोज" की मांग इतनी ज्यादा है कि, संकटग्रस्त प्रजाति वाइल्ड वॉटर बफलो खतरों में आ गए हैं। यह प्रजाति नेपाल के पूर्वी मैदानों में मिलती है। नेपाल एग्रोकल्चरल रिसर्च काउन्सिल के शोधकर्ता भोजान धाकल ने कहा, "हमने देखा है कि, नेपाल के बाजारों में मिलने वाला 70 प्रतिशत मीट बफलो का है। और अगर यह मीट वाइल्ड वॉटर बफलो और पालतू बफलो की संकर प्रजाति का है तो लोग इसके ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं।" नेपाल में इस संकर किस्म की भारी मांग है। स्थानीय समुदाय मानते हैं कि संकर किस्म की मादा ज्यादा दूध देती है। इसलिए भारत के लोग अपने पालतू बफलो, पूर्वी नेपाल के कोशी ट्यूप वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास खुले में संकरण के लिए छोड़ देते हैं। यह नेपाल का अंतिम हैबिटेड है जहाँ वाइल्ड बफलो पाए जाते हैं। रिजर्व के चीफ वॉर्डन रमेश कुमार यादव ने कहा, "पालतू बफलो का वाइल्ड वॉटर बफलो से साथ संकरण गैरकानूनी है। रिजर्व के पास जब हमने पालतू बफलो का सर्वे किया तो हमें कुछ जानवरों में वाइल्ड बफलो के लक्षण दिखे। यह तो संकरण से ही संभव है।" इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नैचर ने कहा कि, वाइल्ड वॉटर बफलो, जिन्हें स्थानीय स्तर पर आर्ना कहा जाता है, की रेंज में कभी बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, श्रीलंका व वियतनाम भी शामिल थे, पर, अब वे सिर्फ नेपाल, भूटान, भारत, कम्बोडिया, म्यानमार और थाईलैण्ड में ही मिलते हैं। गत तीन दशकों में इनकी आबादी 50 प्रतिशत तक घट गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है संकरण। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि, विशुद्ध वाइल्ड वॉटर बफलो पालतू एवं जंगली भैंसों के साथ व्यापक अंतःप्रजनन के कारण संभवतया पहले ही लुप्त हो गए हैं। धाकल कहते हैं कि, "पालतू भैंसों को मीट के लिए संकरित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय उन्हें कुत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाए तो वे अपने मवेशी जंगल में नहीं छोड़ेंगे। पर यह आसान नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं।"

डोभाल की अमेरिकी रक्षा मंत्री से दिल्ली में मीटिंग

नयी दिल्ली 5 जून (वार्ता)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को यहां अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच समुद्री, सैन्य और एयरोस्पेस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार डोभाल ने दो दिन की यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे ऑस्टिन के साथ 'मेक इन इंडिया'

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आये हुये हैं।

और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों की तर्ज पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, सह उत्पादन और स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने पर भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहित वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साझा सुरक्षा हितों और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अपना दृष्टिकोण रखा।

डीडवाना में 3 2 खान धारकों व खनन इंजीनियर के खिलाफ एफ.आई.आर.

यह एफ.आई.आर. डीडवाना की अदालत के आदेश पर दर्ज की गई है

अदालत ने यह आदेश कुचामन निवासी पूर्व सैनिक व पर्यावरण प्रेमी दातार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि, कोलिया और पीर पहाड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है।

डीडवाना, 5 जून। उपखण्ड के कोलिया और पीर पहाड़ी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन को डीडवाना के न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 32 खान धरकों सहित खनिज अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश डीडवाना पुलिस को दिए हैं। कुचामन निवासी पूर्व सैनिक और पर्यावरण प्रेमी दातार सिंह द्वारा दिए गए इस्तरासे के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सभी खान धारकों के साथ खनिज अभियंता के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए। दातार सिंह की वकील सुमन शोखावत के अनुसार क्षेत्र में खनन नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया

बाइक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई है जिसमें राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को अनुमति दे दी गई है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी व्यावसायिक गतिविधि जारी रखें तथा शहर में चल रहे नॉन-ट्रॉसपोर्ट दुपहिया वाहनों के संचालक-समूह के रूप में काम करते रहें।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को मद्देन रखते हुये, उबर तथा रैपिडो नॉन-ट्रांसपोर्ट, जिनमें दुपहिया वाहन भी शामिल हैं, को काम में ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि मोटर वाहन एक्ट तथा मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 के तहत, वैध परमिट प्राप्त किये बिना, राइड-पूलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

'ए.सी.बी. अच्छा काम कर रही...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है, जनता की सेवा करके और जनता के काम करके चुनाव जीता जाता है, इन संस्थाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है। डोटोएस ने कहा- जिन्होंने पेपरलीक किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वह कर दी गई। फिर भी ये किस बामद में इन्का क्या रोल है? समझ में नहीं आ रहा। इमानदारी से कोई मामला बनता बनाएँ, किसी ने जमाखोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग है तो उतकलेफ नहीं है। भजनलाल बिश्नोई के साथ खुद की फोटो वायरल होने के सवाल पर डोटोएस ने कहा कि अब तो ईडी आ गई तो वो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि

जाट, दिनेश चौहान, विनोद कुमार, भंवरी देवी, बजरंग लाल पंवार, किस्तूराम आर्जुन, नानूराम, रामनिवास, जाट, नानूराम, सत्यनारायण शर्मा, रामदेव, रामनिवास, महेंद्र पंवार सहित माइनिंग इंजीनियर नागौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पेंथर्स पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वर्ष पहले राजस्थान में पेंथर पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया था तबतय्य है कि प्रो. भीम सिंह सुप्रसिद्ध राजपूत जनरल जोरावर सिंह के प्रपौत्र थे। शर्मा ने कहा कि भीम सिंह के पूर्वज मूलतः राजस्थान के ही थे।



लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा की भूमिका के लिए मशहूर हुए अभिनेता गूपी पेंटल का सोमवार की सुबह निधन हो गया। उनके परिजनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। दिल और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे पेंटल 78 वर्ष के थे। पंजाब के तरनतारन में चार अक्टूबर, 1944 को जन्मे पेंटल ने फिल्म 'चैतन्य महाप्रभु का निवेशन भी किया। गूपी ने 1975 में रफुचक्कर से फिक्मी जीवन की शुरुआत की थी। उन्हें महाभारत धारावाहिक में शकुनि मामा की भूमिका से सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 'दस परदेस', 'दावा' जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वे टीवी सीरियल्स सी.आई.डी., कर्ण सिंगीनी, राधाकृष्ण का भी हिस्सा थे।

पटना में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दलों को एक साथ लाना आसान नहीं होगा। ऐसे में संयुक्त घोषणा पत्र और समन्वय समिति की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार समन्वयक का भूमिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्र साबित होंगे। त्यागी का तर्क है कि लालू प्रसाद को छोड़कर कांग्रेस से सभी दलों के रिश्ते पूरी तरह सहज नहीं हैं। ममता बनर्जी, अरवविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार और उदय ठाकरे समेत कई नेताओं को एक मंच पर लाने का दायित्व हर कोई नहीं संभाल सकता है।

सी.बी.आई. को बालासोर एक्सप्लोडेंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया था। जैसी पूरी-पूरी संभावना है कि सी.बी.आई. इस केस की जांच करेगी और अगर ऐसा होता है तो जानकारियों (इनपुट) के लिए काफी हद तक सी.आर.एस. पर निर्भर रहना पड़ेगा। विपक्षी दल यह पूछ रहे हैं-क्या जांच के काम में सी.बी.आई. को लाने की कोशिश के पीछे यह विचार है कि रेलवे को दोष मुक्त कर दिया जाये तथा लोगों का ध्यान रेल-सुरक्षा से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दों से हटा दिया जाये?

रेल-सुरक्षा की प्रक्रियाओं में तेजी लाने की जरूरत से जुड़े अनेकानेक मुद्दे हैं। इंडियन रेलवेज की अंदरूनी रिपोर्ट बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉकिंग फेलियर्स, जैसी बालासोर में हुई है, विभिन्न रेलवे जोनों में होती ही रहती हैं। कन्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल (सी.एंड ए.जी.) की 2022 की रिपोर्ट से चौका देने वाले तथ्यों को उजागर करती है कि 2017 से लेकर 2022 तक की 5 साल के अवधि में पूरे भारत में ...ट्रेनों के पटरी से उतरने

की 1000 से ज्यादा घटनाएँ हुई हैं।' जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष", जो नेत्रद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.56 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रु. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रु. रह गया। इसके अलावा, ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिफ्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है।

जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष", जो नेत्रद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.56 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रु. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रु. रह गया। इसके अलावा, ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिफ्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है।

जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष", जो नेत्रद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.56 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रु. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रु. रह गया। इसके अलावा, ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिफ्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है।

जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष", जो नेत्रद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.56 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रु. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रु. रह गया। इसके अलावा, ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिफ्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है।

जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष", जो नेत्रद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.56 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रु. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रु. रह गया। इसके अलावा, ट्रेक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिफ्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है।